श्रीमती सरोज दुबे: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह शराब के विज्ञापन बहुत खूबसूरत तरीके से दिए जाते हैं, एक बहुत सुंदर सा हाथ होता है, नेल पौलिश लगी होती है, क्रिस्टल का सुंदर ग्लास होता है। बड़े ही आकर्षक ढंग से विज्ञापन दिए जाते हैं जिससे लोगों के मन में शराब पीने की चाहत जागती है। मंत्रालय ने एक 'टॉस्क फोर्स' बना रखा है जिसके माध्यम से यह इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन इस टॉस्क फोर्स का काम इतना स्लो है-एक-एक विज्ञापन को रोकने में महीनों लग जाते हैं। नतीजा यह होता है कि विज्ञापन का प्रसारण रुक नहीं पाता और उसका खराब असर समाज में पड़ जाता है। मंत्री जी, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: मैडम, कम से कम एक विज्ञापन तो बंद करा दें जिसमें महिला का कपड़े उतरते हुए दिखाया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is assault on women. Women are subjected to such assaults.

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, मैं इनकी चिंताओं को गंभीरता से लेता हूं अगर कुछ कमी रही है तो मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारे पास कोई प्रि-सेंशरशिप का कानून नहीं है जैसे सिनेमाओं के लिए है।

श्रीमती सरोज दुबे: मैडम, शिकायत पर तो मंत्री जी कार्यवाही कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: मुझे उत्तर देने दीजिए। .....(**व्यवधान**)... मुझे उत्तर देने दीजिए। 18 गानों पर 13 विज्ञापनों पर शो-कॉज हुए हैं और चल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: आप जवाब तो सुन लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: और भी शो-कॉज होंगे और समय से कार्यवाही होगी। ...(व्यवधान)...

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Strategy to reform the Judiciary

*161. DR. AKHILESH DAS: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government have evolved a two pronged strategy on judicial reforms both including appointment of Judges and their accountability;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken or being taken to adopt and implement the same?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (c) The Government is committed to setting up of a National Judicial Commission, which would make recommendations for appointments of Judges/Chief Justice of the Supreme Court and the High Courts as also draw up a Code of Ethics for the Judges.

As part of the process of building up the national consensus to set up the National Judicial Commission, Political parties have been requested to communicate their views in this regard. Setting up of the Commission would involve an amendment to the Constitution of India.

Byrd amendment

*166. SHRI RAJKUMAR DHOOT: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that WTO has upheld the plea of India and 10 other countries that US Continued Dumping and Subsidy Offset Act, 2000 (Byrd Amendment) is inconsistent with WTO agreements on anti-dumping and subsidies and is in violation of global trade rules;

(b) if so, its impact on Indian trade;

(c) whether India would get any compensation from the US Government or companies for the past cases covered under the Act; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) to (d) India, along with eight other co-complainants, including European Communities and Japan, had raised a dispute at the World Trade Organization (WTO) against the "Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA)" of the United States, popularly called the Byrd Amendment, which permitted the US authorities to distribute on an annual basis duties assessed pursuant to countervailing duty/anti-dumping duty order to the affected domestic producers. Subsequently